tax, to file a return of income. Wherever such returns are not filed, notices u/s 142(1) of the Income-tax Act are issued by the assessing officers calling for returns to verify whether, inter-alia, the salary income, inclusive of all tax able alowances have been correctly declared and whether the tax deduction at source has been properly made:

(b) and (c) Under the existing procedure, the salary returns showing income upto Rs. 1.20 lakhs, (where no business income is declared and no brought forward or carry forward losses, except under the head 'House Property', are claimed) are not subjected to detailed scrutiny, but are processed only for prima-facie adjustments. In respect of other cases only about 2 per cent to 3 per cent of the returns are selected for detailed verification. A large proportion of the returns filed in the last two financial years have already been subjeced to these processes which have resulted in proper assessment of the salaries and perquisites; and

(d) No, Sir.

Excise duty on Premium Toilet Soaps

4325. SHRI GOPALSINH G. SOLANKI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that large scale companies get substantial quantities of their premium toilet soaps manufactured in small scale units and evade excise duty by confining themselves only to branding and packing toilet soaps marketed by them;

(b) if so, whether Government would consider treating packing of toilet soaps at par with processing as has been done in case of detergents and subjecting entire sale of branded toilet soaps of excise duty; and

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

सहकारी बैंकों के पूंजी आधार

4326. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या वाणिज्यिक एवं ग्रामीण बैंकों के समान सहकारी बैंकों के पूंजी आधार को सुदृढ करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस पर कब तक कोई निर्णय लेने की संभावना हैं ; और

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार ऐसी कोई योजना बनाने पर विचार करेगी ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति : (क) से (ग) : सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विपरीत, जहां केन्द्रीय सरकार शेय पूंजी में प्रत्यक्ष रूप से अंशदान करती है, राज्य सहकारी बैंकों और जिला सहकारी बैंकों की शेयरधारिता में उनके सदस्यों और राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता हैं । कुछ सीमा तक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिला और राज्य स्तरीय सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान के लिए राज्य सरकारों की सहायता करता हैं ।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक सहकारी प्रणाली के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए राज्य विशिष्ट योजनाएं तैयार कर रहा है और इन योजनाओं के आधार पर उसका राज्य सरकार और राज्य तथा जिला स्तरीय सहकारी बैंकों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव है ताकि राज्य विशिष्ट विकास कार्य योजनाएं कार्यान्वित की जा सकें । इसमें अन्य बातों के साहेतू सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी में अंशदान सहायता के लिए प्रावधान किया जाएगा ।

Excise duty on Cosmetics and Toiletry Goods

4327. SHRI GOPAL SINH G. SOLANKI : Will the Minister of FINANCE be pleased to state :